

न्यायलय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर  
पीठासीन अधिकारी श्री जे०एन०मथुरिया आर.ए.एस.

अपील संख्या 90/17

आर.सी.एम.एस. नम्बर :- 2017/00189

उनवानी :-

1- चाव खॉ

2- रसीद

3- मजीद

4- शरफू

5- रहमती पत्नी सुपेदा

पि स० सुपेदा जाति मेव निवासी उदाका तहसील कामों जिला भरतपुर

वादीगण अपीलान्तान -----

बनाम

1- शेरू पुत्र कलोरा जाति मेव निवासी उदाका तहसील कामों जिला भरतपुर।

2- अफसरदीन पुत्र करीमखॉ जाति मेव निवासी ग्राम उदाका तहसील कामों जिला भरतपुर।

3- अख्तर

4- सहरुल्ली

5-मुफीद

पिसरान कमलखॉ जाति मेव निवासी उदाका तहसील कामों जिला भरतपुर।

असल प्रति वादीगण रेस्पोजेन्टान-----

6- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामों जिला भरतपुर।

7-शाखा प्रबन्धक महोदय पंजाब नेशनल बैंक शाखा भरतपुर।

सतर्तीवी प्रतिवादीगण रेस्पोजेन्टान-----

प्रथम अपील विरुद्ध आज्ञा  
उपखण्ड अधिकारी कामों  
दिनोंक 16.05.2017 व  
मुकदमा सुफेदा बनाम शेरू  
नं०10/14 अन्तर्गत धारा  
223 आर. टी. एक्ट।

Web Copy - Not Official

उपस्थिति:-

- 1- वकील अपीलार्थी श्री पंकज कुमार
- 2- वकील रैस्पो0 श्री हनुमान प्रसाद गोयल

निर्णय

दिनांक 11.04.2019

यह अपील अपीलार्थी द्वारा इस आशय की पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 794/0.33, 795 मिन/0.42 एवम् 1120/0.52 ग्राम उदाका तहसील कामों जिला भरतपुर में स्थित है जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है। विवादित आराजी बाबत अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थागण को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में जाहीर किया कि विवादित खसरा नम्बरो पर सम्वत् 2012 से पहले लगातार अपीलान्ट के पूर्वज चांद खों का कब्जा था और वर्तमान में अपीलान्टगण का कब्जा है। राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के विवादित आराजी के आधे हिस्से पर रैस्पोडेन्टान के पूर्वज कलोरा का नाम दर्ज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना रिकॉर्ड अवलोकन किए वादी अपीलार्थी का वाद खारिज किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा निरस्त करते हुए। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाये व अपीलान्टगण को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये व रैस्पो0 गण के नाम हो रहे इन्द्राज को कलमजन किया जाये।

बचाव में वकील प्रत्यर्था ने अपने बहस में कथन किया कि रैस्पो0 गण के पूर्वज कलोरा का नाम विवादित आराजी पर वर्तमान में दर्ज है। मौके का कब्जा रैस्पो0 का ही है। वादी अपीलान्ट का विवादित आराजी से कोई सरोकार नहीं है। अपीलान्टगण ने गलत तथ्यों के साथ यह दावा पेश किया है। जिसे खारिज करके अधीनस्थ न्यायालय ने कोई भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाये।

बहस उभय पक्ष के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील का मूल बिन्दू यह है कि क्या सहमालिकों में से एक का खुदकाश्त कब्जा उसका स्वयं का कब्जा माना जायेगा अथवा सभी सहमालिकों का खुदकाश्त कब्जा माना जावेगा। मुताबिक जमाबन्दी सम्बत् 2012 में अपीलार्थी के पिता का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज है। इसे सम्बत् 2016 में उभयपक्ष के नाम आधे - आधे दर्ज कर लिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी प्रदर्श - 2 में कृषक के विवरण में खुदकाश्त चांदसिंह दर्ज है। जबकि प्रदर्श-3 जो अन्य खसराओं से सम्बन्धित है, मैं खुदकाश्त मकबूजा मालकान दर्ज है। इन दोनों को सम्मिलित रूप से अवलोकन करने से प्रकट होता है कि प्रदर्श -2 में दर्ज रकबे पर वादी अपीलार्थीगण

का एक मेव कब्जा था। आगामी जमाबन्दी मे किस प्रकार संयुक्त कब्जा दर्ज हुआ रिकॉर्ड से स्पष्ट नही होता है। बहस में यह तथ्य भी आया है कि पूर्व मे जो जायदाद उभय पक्ष के सामूहिक काश्तकारी मे थी, उसे उभयपक्ष मुताबिक हिस्सा बांटकर काश्त करते थे। चूंकि 2012 जो कि राजस्थान काश्तकार अधिनियम के प्रभाव मे आने का वर्ष है मे विवादित आराजी चांदसिंह के नाम खुदकाश्त दर्ज थी। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत् रखे जाने योग्य प्रकट नही होता है।

अतः आदेश है की विवादित आराजी खसरा नम्बर 794/0.33, 795 मिन/0.42 एवम् 1120/0.52 में प्रत्यर्थागण का नाम विलोपित करते हुऐ अपीलार्थीगण को सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी  
भरतपुर

यह आदेश आज दिनांक 11.04.2019 को मेरे द्वारा लिखा या जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

राजस्व अपील प्राधिकारी  
भरतपुर

Web Copy - Not Official